उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल

रिट याचिका (एस/एस) सं0 72 सन् 2022

दिनेश वर्मा और अन्य .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य ..... प्रत्यथीगण।

याचिकाकर्ता की ओर से श्री बी.एस. नेगी व श्री अनिल कुमार जोशी, अधिवक्ता
उत्तराखण्ड राज्य/1 व 3 की ओर से श्रीमती इंदु शर्मा, ब्रीफ होल्डर।
उत्तराखण्ड अधीनस्थ चयन आयोग /2 की ओर श्री पंकज पुरोहित अधिवक्ता।

माननीय शरद कुमार शर्मा, जे (मौखिक)

वर्तमान रिट याचिका के याचिकाकर्ताओं, जिनकी संख्या पांच है, ने 3 जनवरी, 2022 के विज्ञापन के अनुसार, उप निरीक्षकों और निरीक्षाकों (सिविल पुलिस/खुफिया) के पद पर पदोन्नति के माध्यम से चयन आदेशिका आयोजित करने के उद्देश्य से रिट याचिका में भर्ती के तरीके के खिलाफ अपनी शिकायतें उठाई हैं, जिसका व्यथित रूप से मौजूदा रूप से प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा सहारा लिया गया है, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 2, अर्थात यूके अधीनस्थ चयन आयोग द्वारा जारी किया गया है।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत चयन द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया के लिए भर्ती के तरीके के खिलाफ है, जिसे प्रतिवादीओं द्वारा केवल 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित करके अपनाया गया है, जो याचिकाकर्ताओं के अनुसार, यह चयन की आदेशिका की निर्धारित आदेशिका के विपरीत है, जैसा कि 31 जुलाई 2018 को अधिसूचित उत्तराखंड पुलिस उपनिरीक्षक और निरीक्षक (सिविल पुलिस/खुफिया) सेवा नियम 2018 के तहत निर्धारित किया गया है।

3. याचिकाकर्ताओं की दलील है कि याचिकाकर्ता, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के विभिन्न श्रेणियों से संबंधित हैं, साथ ही सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, जो इच्छुक प्रत्यर्थी हैं, जिन्होंने निरीक्षकों और उप निरीक्षकों की पात्रता के मानदंड को पूरा किया है, साथ ही साथ इन पदो पर पदोन्नति की योग्यता के लिये अपनी परीक्षा देने में सक्षम बनाने के

उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई अन्य पात्रता, जैसा कि 3 जनवरी 2022 के विज्ञापन के अनुसरण में प्रतिवादीओं द्वारा किया जाना था, की योग्यता के सभी मानदण्डो को पूर्ण किया है।

4. इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने तर्क देना कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के तहत, राज्य ने उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की खंड 87 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, 31 जुलाई 2018 के आधिकारिक राजपत्र में इसे अधिसूचित करके 2018 के नियमों को जारी किया था, और इसमें भर्ती की प्रक्रिया के विचार के अनुसार, यह प्रावधान किया गया था कि कुल संवर्ग संख्या का 34% पद सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाना है, और याचिकाकर्ताओं के अनुसार सीधी भर्ती की आदेशिका, 2018 के नियमों के नियम 14 के तहत प्रदान की गई थी, और विशेष रूप से, जिस विधि का याचिकाकर्ताओं ने उल्लेख किया था, उसे सीधे भर्ती के पद को लागू करने के लिए उनके अनुसार नियम 14 के उप–नियम (4) के तहत प्रदान किया गया है, जो निम्नवत् है–

> (4) लिखित परीक्षा
>
> उप–नियम (3) के तहत शारीरिक फिटनेस परीक्षण में सफल घोषित सभी उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसके लिए परिशिष्ट में दिया गया है –4''।

5. यदि 2018 के नियमों के नियम 14 के उप–नियम (4) को ध्यान में रखा जाता है, तो इसमें लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए, प्रक्रिया/विधि प्रदान की गई है, और जिस प्रक्रिया का पालन किया जाना है, वह 2018 के नियमों के परिशिष्ट 4 के तहत निहित है, जिसे यहां निकाला गया हैः–

परिशिष्ट–4

(नियम 14 (4) देखें)

सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा–लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी और वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी।परीक्षण का विवरण इस प्रकार हैः–

(1) सामान्य हिंदी (उच्च विद्यालय स्तर)	100 अंक (समय) 1 घंटा, प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक होते हैं
(2) सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता परीक्षण	200 अंक (समय) 02 घंटे)
(ए) सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कसंगतता परीक्षण	50 प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)
(ख) सामान्य जागरूकता	75 प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)

(ग) गणितीय दक्षता (उच्च विद्यालय स्तर) 75 प्रश्न (प्रत्येक प्रश्न) 01 अंक)

(3) प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंकों का नकारात्मक अंकन दिया जाएगा। उत्तर पुस्तिका/ओ. एम. आर. पत्रक कार्बन प्रति के साथ तीन प्रतियां में होगा। ओ. एम. आर. पत्रक की मूल प्रति लिखित परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी द्वारा रखी जा सकती है। संबंधित एजेंसी अपने रिकॉर्ड में फोटोस्टेट कॉपी के साथ एक कार्बन कॉपी भी रखती है। ओ. एम. आर. पत्रक की एक कार्बन प्रति उम्मीदवार द्वारा रखी जा सकती है।लिखित परीक्षा के बाद, उसी की उत्तर कुंजी उत्तराखंड पुलिस की वेबसाइट, यानी uttarakhandpolice.uk.gov.in में प्रकाशित की जाएगी।

(4) लिखित परीक्षा में अनारक्षित श्रेणी और अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को 50% अंक प्राप्त करने होंगे और अनुसूचित जाति/ जनजाति के उम्मीदवारों को 40 % अंक प्राप्त करने होंगे और उसके बाद ही उन्हें योग्यता सूची में शामिल किया जाएगा।''

6. वास्तव में, 2018 के सिद्धांत नियमों ने अपने परिशिष्ट–4 में विचार किया था कि 300 अंकों की कुल लिखित परीक्षा आयोजित की जानी है, जिसे आगे परिशिष्ट संख्या. 4 में दिए गए वर्गीकरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें सामान्य हिंदी के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा और 200 अंकों के सामान्य ज्ञान का आयोजन किया जाना था, जिन्हें आगे सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्कसंगतता परीक्षण के लिए 50 प्रश्नों, सामान्य जागरूकता के लिए 75 प्रश्नों, गणितीय के 75 प्रश्नों में विभाजित किया गया था। दक्षता यानी कुल 200 अंक, जिसमें सामान्य ज्ञान और मानसिक योग्यता परीक्षण से संबंधित विषय भी शामिल थे।

7. रिट याचिका में याचिकाकर्ताओं का दलील था कि यदि चयन की आदेशिका, जिसका सहारा प्रतिवादीओं द्वारा 3 जनवरी 2022 के विज्ञापन के अनुसरण में लिया गया है, लिखित परीक्षा में भाग लेने के लिए संभावित उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये गये थे, वास्तव में, यह 2018 के नियमों के विपरीत है, क्योंकि 3 जनवरी 2022 के विज्ञापन की शर्त के अनुसार, यह केवल 100 अंकों की लिखित परीक्षा थी, जिसे उप निरीक्षक सिविल पुलिस और उप निरीक्षक खुफिया आदि के 65 रिक्त पदों को भरने के लिए आयोजित किया जाना था, जैसा कि उसमें दिया गया था।

8.. याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या. 2 द्वारा जारी विज्ञापन, को उन्होने 2018 के नियमों के परिशिष्ट 5 के तहत अन्यथा सांविधिक रूप से विचार की गई विधि को संशोधित किया था, प्रतिवादी संख्या. 2 के कहने पर आयोजित की जाने वाली प्रस्तावित लिखित परीक्षा को केवल 100 अंकों की लिखित परीक्षा के रूप में सीमित नहीं किया जा सकता था, जैसा कि विज्ञापन में दिया गया है, क्योंकि इसका 2018 के नियमों के विपरीत होने का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और इसके अलावा, यह उस पद के खिलाफ उनके चयन की संभावना को और कम करता है, जिसका विज्ञापन किया गया है, और विशेष रूप से, खंड VII उप खंड (IX) का संदर्भ दिया गया है, जो विभिन्न विषयों के वैकल्पिक प्रश्न के संबंध में 100 अंको का 2 घण्टे का वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रदान करने थे, के सम्बन्ध में विभिन्न विषयों के लिये बहुविकल्पीय प्रश्न, जो लिखित परीक्षा में विस्तृत किये गये हैं, जिन विषयों को उसमें शामिल किया जायेगा, उनका भी विस्तृत विवरण दिया गया है अर्थात हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन को शामिल किया गया।

9. भर्ती प्रक्रिया में उक्त परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए, याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया है कि 3 जनवरी 2022 के विज्ञापन की शर्त संख्या IX को विधि विरूद्ध घोषित किया जाए, जो परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया के विपरीत है जो 2018 के नियमों के तहत प्रदान की गई है। यदि विज्ञापन के खंड IX को ध्यान में रखा जाता है, तो जाहिर है यह 2018 के नियमों के नियम 14 (4) का उल्लंघन प्रतीत होता है, जिसे परिशिष्ट 5 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

10. रिट याचिका पर पहले कुछ मौकों पर तर्क दिया गया था, और अंत में, आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिए जाने का प्रयास किया गया था, कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिया गया तर्क कायम रखने योग्य नहीं हो सकता है, क्योंकि 2018 के नियमों ने 300 अंकों की लिखित परीक्षा को अनिवार्य कर दिया था, जिसका 2018 के नियमों के तहत अनिवार्य रूप से पालन किया जाना था, जिसे उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 की खंड 87 की उप–खंड (1) के तहत बनाया गया था।

11. याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक बार जब अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियम स्वयं भर्ती की एक विधि निर्धारित करते हैं, जिसका सहारा लेना पड़ता है, तो निर्णय के आधार पर, जिसे चयन निकाय द्वारा भर्ती की आदेशिका में बदलाव करके लिया गया था, जिसे याचिकाकर्ताओं के अनुसार नियमों, विशेष रूप से नियमों की खंड 14 (4) के तहत निहित नियमों का उल्लंघन है, को बदला नहीं जा

सकता था।

12 . इसके जवाब में, प्रत्यर्थीध्आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि उत्तराखंड राज्य ने स्वयं एक खंड तैयार किया था, जिसे आधिकारिक राजपत्र में ''**उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग खंड 2014''** के रूप में अधिसूचित किया गया था, जिसमें आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई बहस के अनुसार, उन्होंने प्रस्तुत किया था कि खंड के अध्याय 3 के तहत आयोग के पास निहित शक्तियों के अनुसार, इसने एक अंतर्निहित तंत्र प्रदान किया था, और चूंकि शक्ति स्वयं आयोग के पास निहित है, दिशानिर्देश तैयार करने के लिए, या भर्ती की ''विधि'' से संबंधित मामलों, और इसलिए प्रतिवादी/आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करने का प्रयास किया गया कि 2018 से संशोधित नियम जो एक अधीनस्थ कानून है, हालांकि धारा 87 के तहत बनाये गये उत्तराखंड अधिनियम के संख्या. 20 वर्ष 2014 के अधिनियम की धारा 15 के तहत निहित प्रावधानों पर पूर्वता नहीं होगी और इसलिए आयोग/प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया था कि केवल 100% लिखित परीक्षा आयोजित करने के विज्ञापन में दिए गए चयन के मानदंड, विज्ञापन के खंड IX के अनुसार, जो यहां निकाला गया है, चयन की विधि निर्धारित करने के लिए आयोग द्वारा शक्तियों के प्रयोग के दायरे में थेः–

> **"(ix) लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रमः–**
> चयन के लिए 100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective Type with Multiple Choice) की 02 घन्टे की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन (उत्तराखण्ड की जानकरी सहित) का एक प्रश्नपत्र होगा।''

13. आयोग द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जो यह पद्धति अपनाई गई है, यह खंड 15 की उप–खंड (1) के उप–खंड (ए) के तहत आयोग के पास निहित शक्तियों के अनुरूप है, जिसमें प्रतिवादी/आयोग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क देना गया है कि आयोग के पास भर्ती के ''दिशानिर्देश'' और ''विधि'' से संबंधित मामलों को तैयार करने के लिए अधिनियम द्वारा निहित शक्ति थी। वास्तव में, यह तर्क दिया गया है कि यदि 2018 के नियमों के नियम 14 (4) को इसके परिशिष्ट 5 के साथ पढ़ा जाना है, तो इसे ध्यान में रखा जाता है, यह नियमों का हिस्सा है, जो एक अधीनस्थ कानून है, और इसका मूल अधिनियम के प्रावधानों पर एक प्रमुख प्रभाव नहीं होगा, जहां भर्ती की विधि का चयन और दिशानिर्देशों को निर्धारित करने की शक्तियों को चयन की विधि को विनियमित करने के लिए दिशानिर्देशों और विधि को निर्धारित करने के लिए विशेष रूप से आयोग के अधिकार क्षेत्र में छोड़ दिया गया है। वर्ष 2014 के अधिनियम की खंड 15 के प्रासंगिक प्रावधानों

को यहाँ उल्लिखित किया गया हैः–

अध्याय–III

आयोग की शक्तियाँ और कर्तव्य और व्यवसाय का आवंटन

आयोग की शक्तियाँ और कर्तव्य

15. (1) आयोग के पास निम्नलिखित शक्तियाँ और कर्तव्य होंगे,

अर्थात् –

(क) संबंधित मामलों पर दिशा–निर्देश तैयार करना

भर्ती की विधि।

(ख) परीक्षा आयोजित करना, साक्षात्कार आयोजित करना और उम्मीदवारों का चयन करना।

14. वास्तव में, आयोग के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा जो कहा गया है वह यह है कि 2018 के नियमों के तहत 300 अंकों की लिखित परीक्षा प्रदान करना केवल भर्ती की एक प्रक्रिया है, और इसका योग्यता में पात्रता या योग्यता के पात्रता मानदंड में परिवर्तन के संबंध में कोई संबंध नहीं है, जो नियमों के तहत प्रदान किया गया है, लेकिन यह केवल आदेशिका या विधि है, जिसे नियम 14 के उप–नियम (4) के तहत परिशिष्ट 5 के साथ पढ़ा जाना है, और एक बार पात्रता मानदंड को बदलने में इसका कोई असर नहीं होने के बाद 2018 के नियम, ''दिशा निर्देश'' निर्धारित करने के लिये को चयन निकाय यानी आयोग को दी गई शक्तियों पर प्राथमिकता नहीं होगी। आयोग, अधिनियम की खंड 15 की उप–खंड (1) के उप–खंड (ए) के तहत प्रदान किए गए ''दिशानिर्देश'' और ''भर्ती की विधि'8 से संबंधित मामलों को निर्धारित करने के लिए, क्योंकि प्रतिवादी/आयोग के अनुसार, 100 अंकों की लिखित परीक्षा भी अभी 2014 के नियमों के अनुसार योग्य उम्मीदवारों से आवश्यक योग्यता के सभी क्षेत्रों को शामिल करती है, इसलिए कोई विसंगति नहीं है।

15. प्रतिवादी नं0–2 आयोग के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क को प्रमाणित करने के लिए यू. पी. सामान्य खंड अधिनियम का संदर्भ दिया है, जो स्वतंत्र रूप से अधिनियम को परिभाषित करता है और यू. पी. सामान्य खंड अधिनियम के तहत, इस अधिनियम को इस रूप में परिभाषित किया गया है कि एक प्रक्रिया करने या कराने के लिये विधायिका का जनादेश , जो मौजूदा कानून के अनुरूप है, और अधिनियम के तहत निहित शक्तियों को अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों या विनियमों द्वारा कभी भी ओवरराइड नहीं किया जाएगा या किया जाएगा, जिसे यू. पी. सामान्य खंड अधिनियम 1904

के नियम 4 के उप–नियम (37) के तहत परिभाषित किया गया है, जहां नियमों का अर्थ है एक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में बनाए गए नियमों से है और इसमें विनियमन भी शामिल होंगे जो अधिनियम के तहत एक नियम के रूप में बनाए गए हैं, इस प्रकार नियम या विनियम कानून, और अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधानों को अवहेलना/रद्द नहीं करेगा।

16. यदि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की खंड 87 को ध्यान में रखा जाता है, जिसके तहत 2018 के नियम बनाए गए हैं, तो यह केवल सक्षम प्राधिकरण को नियम तैयार करने की विधायी शक्ति प्रदान करता है, जो यूपी सामान्य खंड अधिनियम 1904 के नियम 4 के उप–नियम (37) के तहत प्रदान की गई परिभाषा के दायरे में आता है, और उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की खंड 87 के तहत बनाए गए नियम, हमेशा एक अधीनस्थ कानून के रूप में गठित होंगे, जो उन पदों के खिलाफ एक प्रक्रिया या भर्ती की विधि को नियंत्रित या विनियमित करते हैं जिनके लिए नियम बनाए गए हैं, जो तत्काल मामले में, उप निरीक्षकों (सिविल पुलिस) के साथ–साथ निरीक्षकों (पुलिस खुफिया विभाग) के लिए पद होते हैं।

17. पक्षकारों के विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, यदि राजपत्र अधिसूचना संख्या. 10/XXVI (3)/2021/78 (1)/2020] जिसे 8 जनवरी 2021 को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था, के लिए कोई संदर्भ दिया जाता है, जिसे ध्यान में रखा जाता है, वास्तव में राज्य द्वारा जारी की गई उक्त अधिसूचना के आधार पर, यह केवल उन पदों पर भर्ती की प्रक्रिया निर्धारित करने से संबंधित है, जो पदोन्नति या सीधी भर्ती के दायरे में आते हैं, 'समूह सी'' पदों पर, जो लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर है, जिसके तहत 2014 के अधिनियम संख्या. 20 की खंड 3 को खंड 3 (एम) तक सीमित कर दिया गया है।

18. प्रतिवादी के विद्वान वकील ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि 2014 का अधिनियम संख्या 20, जहां यह एक अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ''समूह सी'' पदों के संबंध में भर्ती की प्रक्रिया के संचालन के लिए एक असाधारण शक्ति प्रदान करता है, जो लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर हैं, और यह चयन आयोग को पर्याप्त शक्तियां देता है। उस स्थिति में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रदान किए गए निर्दिष्ट तौर–तरीके, जो ''समूह सी'' पदों पर लागू होते हैं, जिन्हें लोक सेवा आयोग के दायरे से बाहर पड़े पद पर पदोन्नति, के माध्यम से भरा जाना है, वे वास्तव में तत्काल मामले में अधिनियम सं। 2014 का 20, और उक्त अधिनियम

की खंड 15 के तहत प्रदान किए गए प्रावधान, जहां यह आयोग को ''भर्ती की विधि'' को संशोधित करने के लिए पर्याप्त शक्ति देता है।उस स्थिति में, 3 जनवरी 2022 के विज्ञापन के खंड IX के तहत लगाई गई शर्तें, जिसमें केवल पुलिस उप निरीक्षकों और निरीक्षकों (नागरिक पुलिस और खुफिया नियम) के लिए पदोन्नति अभ्यास आयोजित करने के उद्देश्यों के लिए 100 अंकों के लिए सीमित लिखित परीक्षा का प्रावधान है, किसी भी स्पष्ट कानूनी दोष से ग्रस्त नहीं हैं, क्योंकि यह चयन आयोग अपनी शक्ति के प्रयोग के दायरे में था, जो 2014 के अधिनियम की खंड 15 के तहत प्रदान किया गया है।

19. चयन आयोग के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि कोई भी शक्ति, जो आयोग द्वारा प्रयोग की जाती है और जो 2014 के अधिनियम के तहत उसमें निहित शक्तियों के भीतर आती है, और विशेष रूप से जब वह पात्रता मानदंड में बदलाव नहीं करती है या चयन के लिए संभावित उम्मीदवारों की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए उत्तराखंड पुलिस अधिनियम की खंड 87 के तहत बनाए गए 2018 के नियमों के तहत प्रदान किए गए पात्रता मानदंड को बाधित करती है, तो आयोग अभी तक 3 जनवरी 2022 के विज्ञापन में खंड IX को शामिल करने की अपनी शक्ति के भीतर था, जो 2014 के नियमों के परिशिष्ट 5 के तहत प्रदान किए गए 300 अंकों के स्थान पर केवल 100 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान करता है, और भर्ती की आदेशिका में किया गया यह संशोधन मनमाना नहीं है, क्योंकि यह एक समान है, जो 3 जनवरी 2022 के विज्ञापन के तहत आवेदन करने के लिये सम्भावित उम्मीदवार होगें और एक बार में यह केवल भर्ती की पद्धति को बदलने तक सीमित है, उम्मीदवार की पात्रता नहीं। यह विज्ञापन का खण्ड IX भेदभावपूर्ण या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप को नहीं करता है, क्योंकि अपनाई गई उक्त पद्धति में विधायी क्षमता का मिश्रण है, और यह मनमाना नहीं है क्योंकि इसे सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू किया गया है। इसलिए यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के उद्देश्य और इरादे को धोखा नहीं देता है।

20. यह न्यायालय उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 और धारा 87 के तहत बनाए गए नियमों की परस्पर क्रिया की तुलनात्मक जांच पर 2014 के अधिनियम के साथ इसके तुलनात्मक अध्ययन पर, चयन निकाय यानी अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा शक्तियों के प्रयोग को नियंत्रित करता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, इस न्यायालय का विचार है कि उत्तर प्रदेश सामान्य खंड अधिनियम की परिभाषा खंड के तहत, जहां एक विशिष्ट वर्गीकरण है, जो अधिनियम, नियमों और विनियमों के विधायी प्रभाव के बारे में किया गया है, जो एक अधिनियम के तहत बनाए गए हैं, यह स्पष्ट है कि अधिनियम के प्रावधानों के

तहत जो प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जो कि प्रमुख प्रक्रिया है, उसका एक बाध्यकारी और प्रबल प्रभाव होगा, और नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया पर प्राथमिकता होगी, जो एक अधीनस्थ विधान के रूप में है, और वह भी विशेष रूप से इसे चयन प्रक्रिया में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू किया गया है।

21. यहां तक कि 2018 के नियमों के नियम 24 के अनुसार, जो यहाँ नीचे उल्लिखित गया है कि:–

सेवा की शर्तें से

राहत

> 24. जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी भी नियम का संचालन किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई का कारण बनता है, तो वह मामले में लागू नियमों में कुछ भी निहित होने के बावजूद, आदेश द्वारा उस नियम की आवश्यकताओं को इस हद तक और ऐसी शर्तों के बशर्ते कर सकती है जो वह मामले से न्यायपूर्ण और न्यायिक मामले में निपटने के लिए आवश्यक समझे।

22. 2018 के नियमों का नियम 24, राज्य के प्राधिकरणों को चयन की विधि के लिए पर्याप्त शक्ति प्रदान करता है, जो है –
2018 के नियमों के अनुसार चयन की आदेशिका में परिवर्तन करने की गुंजाइश का स्वयं उपयोग करने की अनुमति है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त नियमों के अनुसार, और अधिनियम के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन की आदेशिका को संशोधित करने के लिए प्रतिवादीओं द्वारा की गई कार्रवाई को किसी भी तरह से अवैध नहीं कहा जा सकता है और न ही यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि छूट की शक्तियां 2018 के नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार सहित सक्षम प्राधिकरण के पास निहित की गई हैं।

23. इस न्यायालय का विचार है कि याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का दलील स्थिर जा सकता था, यदि प्रतिवादी संख्या. 2 द्वारा शक्तियों का प्रयोग, अधिनियम की खंड 15 के तहत शक्तियों के प्रयोग के दायरे और दायरे से बाहर स्थापित किया गया होता। विशेष रूप से इसका एक उम्मीदवार की पात्रता में कोई बदलाव करने पर असर पड़ता, जिसे चयन की प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए था, और चूंकि आदेशिका या विधि में

बदलाव करके, प्रत्येक 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान करने से, जो विज्ञापन के खंड IX के अनुसार, 2018 के नियमों के परिशिष्ट 5 के तहत आने वाले विषयों के सभी क्षेत्रों को लगभग नियंत्रित करता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा यह संतोषजनक रूप से स्थापित नहीं किया जा सका है, कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन था, क्योंकि यह भाग लेने के अधिकार या पदोन्नति के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने में समानता के अधिकार से वंचित नहीं है, और यदि विज्ञापन के खण्ड– IX के निहितार्थ केवल भर्ती की प्रकिया या पद्धति को संशोधित करने तक सीमित है, जो प्रतिवादी संख्या–2 द्वारा शक्तियों के प्रयोग के दायरे में होगा और इस इसलिये याचीकर्ताओं का तर्क है कि यह उनके विचार के दायरे को कम कर देगा, 2018 के नियमों के परिशिष्ट–5 के तहत लिखित परीक्षा को 300 अंको के स्थान पर केवल 100 अंको के लिये सीमित रखना, इस कारण से स्वीकार्य नहीं है कि याचीकर्तागण को 100 अंको के लिये अलग से परीक्षा नहीं देनी है। लिखित परीक्षा के लिये अंक जैसा कि विज्ञापन द्वारा प्रकाशित किया गया है और एक बार इसे समान रूप से लागू कर दिया गया है, आवश्यक योग्यता और पात्रता मानदंड पर कोई प्रभाव डाले बिना, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं है, और इस प्रकार, 3 जनवरी, 2022 के विज्ञापन के अनुसरण में प्रतिवादी संख्या. 2 द्वारा की जा रही चयन आदेशिका के साथ कोई मनमानेपन नहीं जोड़ा जा सकता है। इसलिए, रिट याचिका में योग्यता का अभाव है, और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है।

(शरद कुमार शर्मा, जे.)

एनआर/

(Translation has been done through AI Tool: ANUVAD) by Neelam Ratra, II Additional District Judge Haldwani, District Nainital.